REPORT OF DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

SHRI AVINASH RAI KHANNA (Punjab): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Fifteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence on 'Demands for Grants (2012-13)' of the Ministry of Defence.

MOTION FOR ELECTION TO THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI SALMAN KHURSHEED): Sir, I move the following Motion:--

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do elect one Member of the Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Shri Janardan Dwivedi from the Rajya Sabha and resolves that the House do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, one Member from amongst the Members of the House to the said Joint Committee, to fill the vacancy."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, matters to be raised with the permission of the Chair. Shri Gehlot.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION (Contd.)

Wheat lying in open in Madhya Pradesh due to lack of adequate supply of gunny bags

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): उपसमाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की योजनानुसार मध्य प्रदेश की सरकार गेहूं की खरीदी कर रही है। मध्य प्रदेश में इस बार बम्पर क्रॉप हुई है। अत्यधिक फसल होने के कारण और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर दिए जाने वाले 100/- रुपए बोनस के कारण किसान खरीदी केन्द्रों पर अधिक मात्रा में गेहूं बेचने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि जो गेहूं खरीदा जा रहा है, उसको भरने के लिए, उसको रखने के लिए और उनको उठाने के लिए केन्द्र की सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए। केन्द्र सरकार ने वचन दिया था कि इस अप्रेल माह के अंत तक 88 बारदाने की गठाने मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराएगी, परन्तु केन्द्र की सरकार ने जो यह बारदान देने का काम प्रारंभ किया, तो अप्रेल तक केवल 17 हजार गांठाने ही उपलब्ध करवा पाई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो गेहूं खरीदा गया है वह खुले में पड़ा है, उसको भरने की जगह नहीं है और केन्द्र की सरकार गेहूं का उठान भी नहीं कर रही है। इस कारण मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करना पड़ा। इन्होंने यहां से आश्वासन दिया, आज भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया, कि हम बारदाना देंगे। यह देंगे, मतलब कैसे देंगे? जो इस माह 81 हजार बारदान देने की इन्होंने सहमति दी थी, उसमें से केवल 17 हजार ही

[श्री थावर चन्द गहलोता<u>।</u>

दिए हैं। अगर इस तरह ही देते रहेंगे, तो गेहूं खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और जो गेहूं खुले में पड़ा है वह बरसात की वजह से खराब हो जाएगा। इसके अलावा जो वहां से आवश्यक उठान होना चाहिए, वह भी केन्द्र की सरकार नहीं कर रही है। इस तरह यह मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में जो गेहूं खरीदा गया है, उसको उठाए और 81 हजार बारदाना देने के लिए जो वायदा किया है, जिसमें से अभी 17 हजार दिए गए हैं, शेष की आपूर्ति तत्काल करे और भविष्य में भी, जैसे मई में जो देने का वायदा किया है, उसको भी दे, अन्यथा गेहूं सड़ेगा, नुकसान होगा। अगर कोई नुकसान होगा, तो उसके कारण किसानों में असंतोष होगा। पिछले 15 दिनों से वहां गेहूं खरीदी बंद है, क्योंकि बारदाना नहीं मिल रहा है और बारदाना न मिलने के कारण सरकार गेहूं खरीद नहीं पा रही है। किसान परेशान हैं, उन्होंने पंजीयन करा दिया है, पंजीयन कराने के बाद उनको सरकार की ओर से सूचना दे दी गई है कि अमुक-अमुक तारीख को आपको आना है और आपको गेहूं देना है, परन्तु बारदाने के अभाव में गेहूं खरीदी रोकना पड़ी है। यह देश के लिए ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० पी.जे. कुरियन): आपका टाइम खत्म हो गया। आप बैठिए, आपका टाइम खत्म हो गया।

Violation of Human rights and unearthing of mass graves in West Bengal

SHRI KUNAL KUMAR GHOSH (West Bengal): Sir, I would like to raise an important issue of regular recovery of human skeletons and mass graves in West Bengal. You can see these cases only in the State of West Bengal and nowhere in the country. All those people have been killed during the time of the former Government. They have been killed only because they were Trinamool Congress supporters and they were not supporting the earlier Government. (*Interruptions*)

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): What is he speaking, Sir? He is levelling criminal charges...(*Interruptions*)

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, he is a new Member and he must be allowed to speak. (*Interruptions*)

SHRI KUNAL KUMAR GHOSH: If you do not allow me to speak today, I will disturb you all throughout the next six years! Please allow me to speak.

Sir, there is a serious case. In the recent past, apart from mass murdering, mass graves have been recovered. Fifteen cases and 60 skeletons have been recovered. My question is: What was the role of the National Human Rights Commission then? In how many cases have they visited the spots and what steps they have taken? From June to December, 2010, the earlier Government was there.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Don't make allegations. You cannot make allegations.